प्रदेश में हाइड्रोजन गैस बनाएंगी 19 कंपनियां

जमीन से लेकर अन्य सुविधाओं को तैयार कर रहा है यूपीनेडा

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में हाइड्रोजन पॉलिसी लागू होने के बाद जल्द ही हाइड्रोजन गैस बनाने वाली 19 परियोजनाएं स्थापित होंगी। यहां तैयार होने वाली हरित हाइड्रोजन गैस का उपयोग खाद कारखाने में किया जाएगा। इसकी कवायद शुरू चल रही है। इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा) को नोडल बनाया गया है।

प्रदेश में वैश्विक निवेश सम्मेलन के दौरान विभिन्न कंपनियों ने हाइड्रोजन गैस परियोजना लगाने पर सहमति जताई थी लेकिन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू नहीं होने के कारण उसके साथ समझौता नहीं हो सकता है। पिछले माह हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में 19 कंपनियों ने नोडल एजेंसी यूपीनेडा से संपर्क किया है। ये कंपनियां यहां हरित हाइड्रोजन गैस तैयार करेंगी। करीब

छह परियोजनाएं बुंदेलखंड में स्थापित करने की है तैयारी

1.95 करोड़ की लागत से शुरू होने वाली इन परियोजनाओं से करीब 1.2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

कंपनियों की पहल के बाद यूपीनेडा इनके लिए पूंजी परिव्यय, भूमि उपलब्धता, बिजली पारेषण आदि के कार्य शुरू कराने की कवायद शुरू कर दिया है। इसमें से करीब छह परियोजनाएं बुंदेलखंड में स्थापित करने की तैयारी है। जबकि एक मिर्जापुर-सोनभद्र में होगी। इसी तरह अन्य परियोजनाएं अलग-अलग इलाके में स्थापित की जाएंगी, ताकि तैयार हरित हाइड्रोजन की आपूर्ति सस्ती दर पर सुगमता से हो सके।

ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता ने बताया कि 19 परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। इन्हें स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जबकि कई अन्य कंपनियों ने इसके लिए सहमति जताया है।

प्रदेश में हाइड्रोजन गैस की स्थिति

अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइजर में पानी को तोड़कर हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। बाद में हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ मिलाकर हरित अमोनिया तैयार होती है। हरित अमोनिया का उपयोग ऊर्जा भंडारण और उर्वरक बनाने व रिफाइनरी में किया जाता है। प्रदेश में हर साल करीब 10 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने की क्षमता की तैयारी है।

बनेंगे दो रिसर्च सेंटर

प्रदेश में हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए शोध और नवाचार भी होगा। इसके लिए दो शोध केंद्र स्थापित करने की भी तैयारी चल रही है।